INDIAN BUSINESS PARTY
इंडियन बिजनेस पार्टी
IBP
www.indianbusinessparty.org

प्रधान मंत्री कार्यालय
Prime Minister's Office
डाक अनुभाग
DAK SECTION
Date 14/6/17

आदरणीय प्रधान मंत्री जी

देश का अन्न दाता किसान आज़ादी के ७० वर्षो बाद भी स्वतंत्र नहीं हुआ है | उसके कृषि कार्य की सभी गतिविधिओ पर किसी न किसी का नियंत्रण है | किसानो की मुख्या समस्या घटती हुए जोत (किसी क्षेत्रफल) है और छोटे छोटे खेतो पर उसके परिवार की निर्भरता |

दुर्भाग्य से राजनितिक दल अपने वोटो की लिए किसानो का क़र्ज़ माफ़ कर देते है | सन 2008 में कांग्रेस सरकार द्वारा 60,000 करोड़ का क़र्ज़ ,फिर आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा ऋण माफ़, 2017 में उत्तर प्रदेश चुनाव में भाजपा द्वारा किया गया वादा जिसमे 36000 करोड़ का ऋण माफ़ किया गया | उत्तर प्रदेश की लगी हुए ऋण माफ़ी की आग अब समस्त भारत को अपने लपटे में लेने को तैयार है | मध्य प्रदेश और महारष्ट्रा एक जीता जागता नमूना है | एक अनुमान के अनुसार उत्तर प्रदेश के चुनाव जितने के लिए की गयी कृषि ऋण माफ़ी योजना की सम्पूर्ण राष्ट्र को लगभग 5 लाख करोड़ कीमत चुकानी पड़ेगी ,यानी की एक साल की राजस्व का लगभग आधा | यह सुनिश्चित है कि हर राजनितिक दल चुनाव जितने के लिए कृषि ऋण माफ़ी को एक वोट पाने के हथियार के रूप में जरूर उपयोग में लाएँगे | यह दुखद है की कारोबारी वर्ग को इस राजनितिक निर्णयों की कीमत चुकाने पड़ती है |

इंडियन बिज़नेस पार्टी ,किसानो को एक कारोबारी मानती है और कृषि क्षेत्र की सुधर हेतु कुछ प्रस्ताव रखती है

1. देश की एक तिहाई किसान किराय की खेत पर कृषि कार्य करते है | भारत में कृषि भूमि को किराए पर देना कानूनी रूप से प्रतिबंधित है | जमींदार लोग अवैध रूप से छोटे छोटे किसानो को अपनी भूमि बटाई पर दे देते है, जिसकी सरकारी रिकॉर्ड में कोई लिखा पड़ी नहीं | किरायदार किसान कि विडम्बना यह है कि उसे न तो बैंक ऋण ही मिल पता है और न ही फसल के नुकसान होने पर मुआवज़ा | बेचारा किरायदार किसान पुरे साल सूद खोरो से ऋण ले ले कर खेती करता है और साल की आखिर में उसे सिर्फ शून्य मिलता है | सरकार को तुरंत एक कानून बना कर कृषि खेतो की किराएदारी को वैधानिक रूप देना चाहिय तथा किराय की खेती पर बैंक द्दारा ऋण मिलना चाहिय |

2. कॉर्पोरेट और कॉन्ट्रैक्ट खेती पर कानून ला कर इस प्रकार की खेती को वैधानिक बनाना चाहिय |

3. सरकार किसानो की न्यूनतम आय को सुनिश्चित करे और फसलों की कीमत का 85 % भाग किसानो को मिले और शेष 15 % बिचौलिओं को | अभी यह अनुपात उल्टा है |

Pragati Tower, 26 Rajendra Place, New Delhi-110008, INDIA.
+91-11-25784221 +91-7042828540 info@indianbusinessparty.org, indianbusinessparty@gmail.com
www.facebook.com/indianbusinessparty twitter.com/InBusinessParty www.linkedin.com/in/indianbusinessparty

4. किसानो को कृषि पर निर्भरता कम करके स्वरोजगार अपनाने की लिए प्रोत्साहित करना चाहिय ।

5. ऐसा कानून बनाना चाहिय की कृषि ऋण माफ़ी योजना चुनावी घोषणा पत्र का विषय न बने ।

6. छोटे छोटे खेतो पर सहकारी (co -operative) पद्धति को पुनः जीवित किया जाय ।

सरकार को यह ध्यान में रखना चाहिय कि अन्न प्रदाता किसानो को कोई विकल्प नहीं है । यदि देश का किसान अशांत है तो देश की सीमा भी सुरक्षित नहीं हो सकती क्यूंकि अधिकांश सैनिक कृषक परिवार से आते है ।

आशा है कि भारत सरकार आपके नेतृत्व में किसानो की समस्याओ का स्थाई समाधान खोजने में सफर रहेगी और देश अन्न के अन्न की भंडार सदैव भरे रहेंगे ।

सादर

वी के बंसल
राष्ट्रीय अध्यक्ष

दिनांक 14जून 2017

सेवा में
माननीय प्रधान मंत्री जी
भारत सरकार
नई दिल्ली